हरियाणा सरकार

प्राथमिक शिक्षा विभाग

की

वर्ष 1995-96

की

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-9819
Date...... 03-03-98.

NIEPA DC
D09819

REVIEW OF ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF THE PRIMARY EDUCATION DEPARTMENT FOR THE YEAR 1995-96

Education plays a vital role in re-construction of society and upliftment of Nation. Keeping this fact in view Directorate of Primary Education has been making all out efforts to bring all the children in the age group of 6-11 years of age into the fold of Primary Education. To achieve the target of universalisation of Primary Education in State, the State Government has made primary schooling facilities available at a walking distance.

During the year 1995-96, 27 pre-primary schools/balwaries, 5501 primary schools, 3955 primary schools attached to Middle/High/Senior Secondary Schools were functioning in the State. The total number of children studying at pre-primary and primary, stages was 11329 and 18,95,897 respectively in Government and recognised schools. Over all percentage of school going children in the age group of 6-11 years was 84.87 and this percentage in respect of scheduled castes children was 115.40. About 4.48 lacs children are enrolled in unrecognised primary schools. With the result the enrolment ratio of school going children in the age group of 6-11

years has risen to 105%. An amount of Rs. 16571.27 Lacs was spent on primary education during the year 1995-96. An amount of Rs. 322.94 lacs was given as Grant in-Aid to non-government recognised aided primary schools in the State.

With a view to enroll and retain children particularly girls, a number of incentive schemes were continued for the year under report. A sum of Rs 190.00 lacs was spent on attendance prizes to 1.58 lacs girls. An amount of Rs. 281.67 lac was spent on providing free uniform, text books and stationery. 14198 children of nomadic tribes were given special attendance allowance for which state spent Rs. 30.91 lacs.

Alogwith expansion of primary education, steps were taken for improvement of quality education, this includes, in service training of teachers/head teachers, holding of different competition at Block, District and State levels, school cleanliness competition at Block level etc. State Government has adopted "District Primary Education Project" with the help of World Bank. Under this project 85% of total expenditure is borne by the World Bank while remaining 15% of the expenditure is funded by the State. 201 new schools were opened during the year under report.

During the year 1995-96 Sh. Phool Chand Mullana was the Education Minister, Sh. R.L. Sudhir, I.A.S., was the Financial Commissioner and Secretary to Government, Haryana, Education Department, Chandigarh, Sh. P.K. Mahapatra held the office of the Director Primary Education, Haryana.

VISHNU BHAGWAN

Financial Commissioner and
Secretary to Government, Haryana,
Education Department, Chandigarh.

प्राथमिक शिक्षा विभाग की वर्ष 1995-96 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा

समाज के पुनर्गठन एवं राष्ट्र उत्थान में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस तथ्य के दृष्टिगत प्राथमिक शिक्षा निदेशालय 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने के लिये भरसक प्रयास कर रहा है। राज्य में प्राथमिक शिक्षा को सार्वजनीन बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार ने पैदल दूरी पर प्राथमिक विद्यालय की सुविधायें उपलब्ध करवाई हैं।

वर्ष 1995-96 के दौरान राज्य में 27 पूर्व प्राथमिक विद्यालय/बालवारियां, 5501 प्राथमिक विद्यालय तथा 3955 प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक/उच्च वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध, कार्यरत थे ' सरकारी तथा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले कुल बच्चों की संख्या क्रमश: 11329 और 1895897 थी। 6-11 वर्ष के आयु के वर्ग के विद्यालयों में जाने वाले बच्चों की कुल प्रतिशतता 84.87 थी और अनुसूचित जाति के बच्चों का प्रतिशतता 115.40 थी ' लगभग 4.48 लाख बच्चे अमान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में दाखिल हैं। इसके परिणामस्वरूप 6-11 वर्ष के आयु वर्ग के विद्यालय जाने वाले बच्चों का दाखिला अनुपात 105 प्रतिशत बढ़ गया है। वर्ष 1995-96 के दौरान प्राथमिक शिक्षा पर 16571.27 लाख रुपये की राशि खर्च की की गई। 322.94 लाख रुपये का राशि राज्य में गैर सरकारी मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों को सहायता-अनुदान के रुप में दी गई हैं।

बच्चों, विशेषतया लड़कियों को दाखिल करने और उनकी पढ़ाई जारी रखने के दृष्टिगत रिपोर्टाधीन वर्ष के लिये अनेक प्रोत्साहन स्कीमें जारी रखी गई। 190.00 लाख रुपये की राशि 1,58 लाख लड़कियों को उपस्थिति पुरस्कार देने के लिये खर्च की गई। 281.67 लाख रुपये की राशि

निशुल्क वर्दियां, पाठ्य पुस्तकें और लेखन सामग्री देने पर खर्च की गई। घुमन्तु कबीलों के 14198 बच्चों को विशेष उपस्थिति भत्ता दिया गया, जिसके लिये राज्य ने 30.91 लाख रुपये खर्च किये।

प्राथमिक शिक्षा के बिस्तार के साथ-साथ गुणात्मक शिक्षा में सुधार लाने के लियै उपाय किये गये। इन उपायों में अध्यापकों/मुख्यअध्यापकों का सेवा-कालीन प्रशिक्षण, खण्ड जिला और राज्य स्तर पर विभिन्न प्रतियोगितायें आयोजित करवाना, शामिल है। राज्य सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से "जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना" अपनाई है। इस परियोजना के अन्तर्गत कुल खर्च का 85 प्रतिशत विश्व बैंक द्वारा किया जाता है जबकि शेष 15 प्रतिशत खर्च के लिये राज्य द्वारा निधियां दी जाती हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 201 नये विद्यालय खोले गये।

वर्ष 1995-96 के दौरान श्री फूल चन्द मुलाना, शिक्षा मन्त्री, श्री आर0 एल0 सुधीर, आई0 ए0 एस0, वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग थे। श्री पी0 के0 महापात्रा, निदेशक, प्राथमिक शिक्षा हरियाणा के पद पर थे।

विष्णु भगवान,
वित्तायुक्त एवं सचिव,
हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग।

वर्ष 1995-96 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

अध्याय पहला

प्रशासन एवं संगठन

वर्ष 1995–96 में श्री फूल चन्द मुलाना ने शिक्षा मन्त्री के रूप में शिक्षा विभाग का कार्य किया।

सचिवालय स्तर पर

रिपोर्टाधीन अवधि में वित्तायुक्त एवं सचिव, शिक्षा विभाग के पद पर श्री आर0 एल0 सुधीर, आई.ए.एस. ने कार्य किया तथा संयुक्त सचिव के पद पर श्री अमित झा, आई.ए.एस. ने कार्य किया।

निदेशालय स्तर पर

प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए वर्ष 1988 में हरियाणा सरकार द्वारा पृथक प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का गठन किया गया था।

रिपोर्टाधीन अवधि में निदेशक प्राथमिक शिक्षा के पद पर श्री पी0 के0 महापात्रा, आई. ए.एस. ने कार्य किया। निम्न पदों पर नियुक्त अधिकारियों द्वारा निदेशालय के कार्य को सुचारू रूप से चलाने में निदेशक महोदय को सहयोग दिया गया।

क्रमांक	पद	पदों की संख्या
1.	अतिरिक्त निदेशक	1
2.	संयुक्त निदेशक	1
3.	उप निदेशक	1
4.	प्रशासनिक अधिकारी प्राथ0 शिक्षा	1
5.	रजिस्ट्रार प्राथमिक शिक्षा	1

जिला स्तर पर

राज्य के प्रत्येक जिले में प्राथमिक शिक्षा का विकास, प्रशासन और नियन्त्रण का उत्तरदायित्व जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी पर है। जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी अपने जिले में प्राथमिक शिक्षा का विकास तथा राज्य की शिक्षा नीतियों को समय समय पर निदेशालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कार्यरूप देते हैं।

खण्ड स्तर पर

प्राथमिक विद्यालयों के निरीक्षण तथा प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य को 124 शिक्षा खण्डों में बांटा गया है। खण्ड शिक्षा अधिकारी अपने अपने खण्ड में प्राथमिक शिक्षा के विकास तथा प्राथमिक विद्यालयों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने जिले के प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के प्रति उत्तरदायी हैं।

राजकीय प्राथमिक विद्यालय

सभी राजकीय प्राथमिक विद्यालयों का प्रशासनिक प्रबन्ध उनके हैड टीचर के माध्यम से चलाया जाता है। सभी अध्यापक अपने अपने विद्यालयों में विद्यार्थियों को सुचारू रूप से शिक्षा देने तथा उनके शैक्षिक, मानसिक और शारीरिक विकास के लिए खण्ड शिक्षा अधिकारी/जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी/शिक्षा विभाग के प्रति उत्तरदायी हैं।

शिक्षा पर व्यय

वर्ष 1995–96 में प्राथमिक शिक्षा पर 16571.27 लाख रुपये की राशि खर्च की गई। इसमें से गैर योजना पक्ष पर 12824.94 लाख रुपये तथा योजना पक्ष पर 3746.33 लाख रुपये, जिनमें 168.83 लाख रुपये केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के सम्मिलित हैं, व्यय हुये।

अराजकीय विद्यालयों को अनुदान

अराजकीय विद्यालयों में शिक्षा कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के

लिए सरकार उदारतापूर्वक अनुदान देती है । अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत राज्य सरकार, अराजकीय विद्यालयों को उनके घाटे का 75 प्रतिशत अनुदान देती है। रिपोर्टाधीन अवधि में अराजकीय विद्यालयों को 172.49 लाख रुपये की राशि अनुरक्षण अनुदान के रूप में दी गई। अराजकीय विद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमानों में परिवर्तन के कारण कोठारी अनुदान के अन्तर्गत 150.45 लाख रुपये की राशि कोठारी अनुदान के रूप में दी गई ।

हरियाणा चाईल्ड वैलफेयर कौंसिल को 1.42 लाख रुपये की राशि अनुदान के रूप में दी गई । राज्य में अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाली लड़कियों की फीस की प्रतिपूर्ति के लिए 6,13,260/- रुपये की राशि दी गई ।

दूसरा अध्याय

पूर्व प्राथमिक शिक्षा

पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3–6 आयु वर्ग के लड़के और लड़कियों को दी जाती है । राज्य में इस समय शिशु शिक्षा के लिए 7 पूर्व प्राथमिक विद्यालय सरकारी क्षेत्र में स्थापित हैं । राज्य में समाज के पिछड़े/औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य कर रहे श्रमिकों के शिशुओं की देखरेख एवं सुविधा के लिए 20 राजकीय बालवाड़िया कार्यरत हैं । इसके अतिरिक्त कुछ प्राथमिक, मिडल तथा उच्च विद्यालय में भी पूर्व प्राथमिक कक्षाएं चलती हैं । रिपोर्टाधीन अवधि में पूर्व प्राथमिक विद्यालयों तथा बालवाड़ियों में छात्र संख्या निम्न प्रकार थी :–

छात्र संख्या	लड़के	लड़कियां	जोड़
1. कुल छात्र संख्या	6631	4698	11329
2. अनु०जाति के छात्रों की संख्या	396	321	717

अध्यापकों की संख्या

रिपोर्टाधीन अवधि में पूर्व प्राथमिक विद्यालयों/बालबाड़ियों में अध्यापकों की संख्या निम्न प्रकार थी :–

अध्यापक	पुरुष	महिलाएं	जोड़
1. कुल अध्यापक	2	32	34
2. अनु०जाति के अध्यापकों की संख्या	—	—	—

प्राथमिक शिक्षा

प्राथमिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा है । इसे राज्य के प्रत्येक बच्चे को उपलब्ध करवाना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य में इसके विस्तार एवं विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1995–96 में लड़कियों के लिए 100 नये राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का लक्ष्य था जिसके समक्ष 201 राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोले गये ।

इस समय राज्य में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा 1.22 कि०मी० की परिधि में उपलब्ध हैं ।

रिपोर्टाधीन अवधि में प्राथमिक शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े निम्न प्रकार से हैं :—

प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	लड़के	लड़कियां	जोड़
सरकारी	4288	1033	5321
गैर सरकारी	163	17	180
जोड़	4451	1050	5501

छात्र संख्या विद्यालय अनुसार	लड़के	लड़कियां	जोड़
1. कुल छात्र संख्या	404656	420645	825301
1. अनु०जाति के छात्रों की संख्या	116019	122990	239009
स्तर अनुसार छात्र संख्या कक्षा 1 से 5			
1. कुल छात्र संख्या	1025420	870477	1895897
2. अनु०जाति के छात्रों की संख्या	262985	228607	491592
अमान्यता प्राप्त विद्यालयों में छात्र संख्या	243807	204313	448120

6–11 आयु वर्ग के बच्चों की विद्यालयों में प्रतिशतता
(सरकारी एवं गैर सरकारी मान्यता प्राप्त)

1. कुल छात्रों की प्रतिशतता	86.98	82.52	84.87
2. अनु० जाति के छात्रों की प्रतिशतता	116.98	113.62	115.40
अध्यापकों की संख्या	पुरुष	महिला	जोड़
1. कुल अध्यापक	9543	8398	17941
2. अनु० जाति के अध्यापकों की संख्या	945	264	1209

नामांकन अभियान

6–11 वर्ष की आयु वर्ग के अधिक से अधिक बच्चों को विद्यालयों में लाने के लिए प्रति वर्ष अप्रैल मास में छात्र नामांकन अभियान के अन्तर्गत विद्यालयों से बाहर के बच्चों को विद्यालय के उपस्थिति पटट् पर लाया जाता है ।

वर्ष 1995–96 में नामांकन अभियात के लिए 16.00 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था बजट में करवाई गई । इस राशि में से 4.00 लाख रुपये की राशि अधिक से अधिक बच्चे स्कूलों में दाखिल करने के लिए इलैक्ट्रोनिक माध्यमों से व्यापक प्रचार करने के लिए खर्च की गई । शेष राशि विद्यालयों में बच्चों विशेषकर लड़कियों को प्राथमिक श्रेणियों में दाखिल करने तथा विद्यालय शिक्षा को जारी रखने में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों, संस्थाओं एवं विद्यालयों को नकद पुरस्कार देने के लिए खर्च की गई ।

शाखा प्राथमिक विद्यालय

जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी ऐसे गांवों में जहां 30 या इससे अधिक बच्चे पढ़ने के लिए उपलब्ध हैं, शाखा प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए सक्षम हैं ।

विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के लिए एस.एस.एस. बोर्ड द्वारा 6204 पदों के लिए विज्ञापन दिया गया था और 5475 अध्यापकों के नाम नियुक्ति हेतू जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों को भेजें गए ।

अध्याय तीसरा

विविध

छात्रों को प्रोत्साहन

राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में पहली से पांचवीं कक्षा तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जाती है। प्रथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे अनुसूचित जाति तथा कमजोर वर्ग के छात्र/छात्राओं को 10 रुपये प्रति छात्र, वर्ष में एक बार लेखन सामग्री क्रय हेतु दिये जाते हैं। वर्ष 1995--96 में इस स्कीम के अन्तर्गत 48.45 लाख रुपये की राशि खर्च की गई। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों तथा कमजोर वर्ग की लड़कियों की मुफ्त बर्दी देने की स्कीम आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992–97 में भी जारी रहेगी। वर्ष 1995–96 में इस स्कीम के अन्तर्गत 195.32 लाख रुपये की राशि खर्च की गई जिससे 2.17 लाख लड़कियों को लाभ पहुंचा। इस वर्ष 190.00 लाख रुपये उपस्थिति पुरस्कार के अन्तर्गत दिये गये जिससे 1.58 लाख लड़कियां लाभान्वित हुई। अनुसूचित जाति की छात्राओं को 10 रुपये प्रतिमास छात्रावृति भी दी जाती है।

इसके अतिरिक्त खानाबदोश जाति के बच्चों के लिये विशेष प्रोत्साहन स्कीम दिसम्बर 1988 में लागू की गई। इस स्कीम के अन्तर्गत घुमन्तु जाति के प्रत्येक बच्चे को स्कूल आने पर एक रुपया प्रतिदिन दिया जाता है। वित्त वर्ष 1995–96 में इस स्कीम के तहत 30,91 लाख रुपये की राशि खर्च की गई। जिससे 14198 बच्चे लाभान्वित हुए। अनुसूचित जातियों तथा समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए बुक बैंक स्कीम के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र के आरम्भ में नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाती हैं। बुक बैंक स्कीम के अन्तर्गत वित्त वर्ष 1995–96 में 37.50 लाख रुपये की

कुल राशि में से 13.50 लाख रुपये नान प्लान तथा 24.00 लाख रुपये की राशि प्लान पक्ष पर खर्च की गई जिससे 1.87 लाख बच्चे लाभान्वित हुए ।

अस्वच्छ कार्यों में नियुक्त कर्मचारियों, अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई जारी रखने के लिए हरियाणा सरकार कल्याण विभाग द्वारा एक नई योजना आरम्भ की गई जिसके अन्तर्गत प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे बच्चों को शैक्षिक वर्ष में प्रोत्साहन हेतु 10 मास के लिए 25/- रु० मासिक वजीफा तथा एक बार 300/- रु० की तदर्थ ग्रांट दी गई । वर्ष 1995-96 में इस स्कीम के अन्तर्गत 70.49 लाख रुपये खर्च हुए तथा इससे 11950 बच्चों को लाभ मिला । एक अन्य स्कीम जो अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा चलाई जाती है, के अधीन विमुक्त जाति के बच्चों को 10 रुपये प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी स्टाईफण्ड देने पर वर्ष 1995-96 में 6.65 लाख रुपये खर्च किये जिससे लगभग 4785 बच्चे लाभान्वित हुए ।

प्राथमिक विद्यालयों को बच्चों के लिए और अधिक सुविधाजनक बनाने हेतु सरकार द्वारा प्रति वर्ष विद्यालयों में दरी-पट्टी उपलब्ध करवाने का प्रोग्राम है । पंचवर्षीय योजना 1992-97 में इस स्कीम के तहत 250 लाख रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है । वर्ष 1995-96 में इस स्कीम के अन्तर्गत 50 लाख रुपये खर्च किए गये ।

भवन निर्माण कार्य

राज्य सरकार प्राथमिक विद्यालयों को भवन उपलब्ध करवाने के प्रति काफी जागरूक है । वर्ष 1995-96 में इसके लिए 200 लाख रुपये की राशि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गई । आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस उद्देश्य के लिए 1150 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था का प्रस्ताव है । जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कक्षा कक्ष/भवनों के निर्माण के लिए 3.00 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई गई तथा 40.00 लाख रुपये की राशि राजकीय प्राथमिक विद्यालयों की मुरम्मत एवं रख रखाव हेतु जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों को दी गई ।

खेल एवं स्वास्थ्य शिक्षा

खेलों तथा स्वास्थ्य शिक्षा को प्राथमिक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष खेल के सामान आदि के लिए 15 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की जाती रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत 500 विद्यालयों को लगभग 3000/– रु० की राशि की खेल सामग्री प्रति स्कूल के हिसाब से दी जा रही है। वर्ष 1995–96 में इस योजना के अन्तर्गत 12.00 लाख रुपये की राशि खर्च की गई।

केन्द्र संचालित परियोजना

लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और स्कूल छोड़ देने वाली लड़कियों की संख्या को कम करने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 1994–95 में 4 जिलों (हिसार, सिरसा, कैथल तथा जीन्द) जिनमें महिला साक्षरता दर बहुत कम थी, केन्द्र संचालित परियोजना जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आरम्भ किया गया। यह परियोजना 2001 ईसवीं तक चलनी है। इस परियोजना की कुल लागत का 85 प्रतिशत भाग सहायता अनुदान के रूप में भारत सरकार द्वारा तथा शेष 15 प्रतिशत खर्चा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। वर्ष 1995–96 में इस परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 1560.93 लाख रुपये की राशि दी गई और 250.00 लाख रुपये की राशि राज्य सरकार द्वारा खर्च की गई। इस परियोजना से शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने में भी बहुत सहायता मिलेगी।

गुणात्मक सुधार कार्यक्रम

रिपोर्टाधीन अवधि में प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर गुणात्मक सुधार लाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा एक विस्तृत कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1995–96 में 10.00 जे० बी० टी अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया गया तथा इस पर 20.00 लाख रुपये की राशि खर्च की गई। प्राथमिक विद्यालयों के कार्य में सुधार विषयक एक और उपाधार कार्यक्रम राज्य में लागू किया गया है। जिसके अन्तर्गत सभी जिला एवं खण्ड शिक्षा अधिकारियों को दो दो राजकीय प्राथमिक विद्यालय अडॉप्ट

करके उन्हें आदर्श विद्यालय बनाने के लिए कहा गया है ताकि आदर्श विद्यालय के आसपास के विद्यालयों के लिए अनुकरणीय बन सकें । आरम्भ में वर्ष 1992–93 में 280 राजकीय प्राथमिक विद्यालय अडॉप्ट किये गये थे । 8वीं पंचवर्षीय योजना में 700 स्कूल अडॉप्ट करने का लक्ष्य है ।

शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से पांचवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा जिला स्तर पर आयोजित की गई । एक अन्य योजना के अन्तर्गत शिक्षित वर्ष के शुरु में विद्यालय योजना का बनाना और निरीक्षण योजना बनाने के साथ साथ विभिन्न विषयों में मासिक परीक्षा लेना और विद्यार्थी प्रगति रजिस्टर मेनटेन करना शामिल है ताकि बच्चों की पढ़ाई की प्रगति बारे माता पिता को सूचना मिलती रहे । पाठन की प्रवृति को प्रोत्साहित करने हेतु स्कूल समय सारणी में पुस्तकालय पीरियड का प्रावधान किया गया । इस कार्य-क्रम के अन्तर्गत सुलेख प्रतियोगताएं, खण्ड तथा जिला स्तर पर आयोजित करवाना, वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, ड्रामा, कविता उच्चारण, समाचार पत्र पढ़ने की प्रतियोगिता तथा प्रश्न मंच आदि शामिल हैं । इसके अलावा शिक्षा सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वच्छता प्रतियोगिता का भी वर्ष 1995-96 में आयोजन किया गया और 2.00 लाख रुपये की राशि की प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले स्कूलों को नकद पुरस्कार देने पर खर्च की गई सुलेख प्रतियोगिता एवं मौखिक अभिव्यक्ति सम्बन्धी इन कार्यक्रमों पर बर्ष 1995-96 में क्रमशः 0.50 लाख तथा 0.50 लाख रुपये की राशि खर्च की गई । बच्चों के शारीरिक विकास, उनमें आपसी सहयोग व प्रतिस्पर्धा की भावना की जागृत करने के लिए खण्ड तथा जिला एवं राज्य स्तर पर खेल-कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया । राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन 21-12-95 से 23-12-95 तक कुरूक्षेत्र में किया गया । इसमें राज्य के सभी जिलों के लगभग 3000 बच्चों ने भाग लिया। 500 कब्स तथा बुलबुलों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया।

मध्याह्न पोषाहार

भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 1995 से राष्ट्रीय पोषाहारिक सहायता कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा के बच्चों के लिए लागू किया गया । इस कार्यक्रम

का उदेदश्य प्राथमिक शिक्षा के बच्चों का शिक्षा के प्रति रूझान बढ़ाना है, छात्र संख्या में बढ़ौतरी करना तथा उपस्थिति को सुनिश्चित करना तथा समाज में बच्चों के पौष्टिक स्तर में सुधार लाना है ।

इस स्कीम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जिस राज्य में पका पकाया भोजन देना हो वहां 100 ग्राम खाद्यान्न प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन के हिसाब से तथा जिस राज्य में सूखा खाद्यान्न बंटवाया जाये वहां 3 किलोग्राम गेहूं/चावल प्रति बच्चा, प्रतिमास के हिसाब से दिया जाता है । हरियाणा राज्य में स्कूली बच्चों को वर्ष 1995-96 में पका पकाया भोजन उपलब्ध करवाया गया ।

खाद्यान्न प्रत्येक मास के अन्तिम कार्यदिवस को अध्यापकों द्वारा उन छात्रों में बांटा जाता है, जिनकी हाजरी 80 प्रतिशत होती है । इस योजना के लागू होने से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों की संख्या में बढ़ौतरी हुई है । यह योजना भारत सरकार की सहायता से चलाई जा रही है । वर्ष 1995-96 में इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा राज्य के छः जिलों (भिवानी, हिसार, महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी, रोहतक तथा सिरसा में 3209 प्राथमिक स्कूलों में 5,91,824 बच्चों को पका पकाया भोजन उपलब्ध कराया गया ।

नैतिक शिक्षा

प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों में नैतिक मूल्यों को बढावा देने के लिए नैतिक शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाना शुरू किया गया ।

सारणी-1

वर्ष 1995-96 में जिलेवार प्राथमिक विद्यालयों की संख्या ।

क्र० सं०	जिले का नाम	स्वतन्त्र प्राथमिक विद्यालय			संलग्न प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	कुल प्राथमिक विद्यालय
		लड़के	लड़कियां	जोड़		
1	2	3	4	5	6	7
1.	अम्बाला	324	48	372	196	568
2.	भिवानी	254	56	310	263	573
3.	फरीदाबाद	333	80	413	261	874
4.	गुड़गांव	447	124	571	278	849
5.	हिसार	346	121	467	441	908
6.	जीन्द	151	93	244	304	548
7.	कैथल	151	48	199	169	368
8.	करनाल	298	47	345	179	524
9.	कुरुक्षेत्र	295	60	355	130	485
10.	महेन्द्रगढ़	300	63	363	212	575
11.	पंचकुला	119	35	154	70	224
12.	पानीपत	128	22	150	122	282

1	2	3	4	5	6	7
13.	रिवाड़ी	260	35	295	154	449
14.	रोहतक	286	71	357	451	808
15.	सिरसा	209	96	305	244	549
16.	सोनीपत	222	14	236	327	563
17.	यमुनानगर	328	37	365	144	509
	जोड़ :	4451	1050	5501	3955	9456

सारणी–2

वर्ष 1995–96 में जिलेवार तथा संस्थानुसार अध्यापकों की संख्या (केवल स्वतन्त्र प्राथमिक विद्यालय)

क्र० सं०	जिले का नाम	कुल अध्यापक संख्या			केवल अनुसूचित जाति के अध्यापकों की संख्या		
		पुरुष	महिला	जोड़	पुरुष	महिला	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अम्बाला	348	775	1103	30	74	104
2.	भिवानी	488	463	951	38	16	54
3.	फरीदाबाद	1040	571	1611	116	17	133
4.	गुड़गांव	963	705	1668	62	7	69
5.	हिसार	850	844	1794	142	14	156
6.	जीन्द	809	348	1157	73	10	83
7.	कैथल	425	229	654	31	3	34
8.	करनाल	485	539	1024	56	14	70
9.	कुरुक्षेत्र	387	415	802	43	11	54
10.	महेन्द्रगढ़	681	329	1010	64	6	70
11.	पंचकुला	111	321	432	15	9	24
12.	पानीपत	354	321	675	28	3	31

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	रिवाड़ी	538	292	830	46	3	49
14.	रोहतक	708	873	1581	54	21	75
15.	सिरसा	364	384	748	64	9	73
16.	सोनीपत	512	549	1061	32	42	74
17.	यमुनानगर	380	460	840	51	5	56
	जोड़ :	9543	8398	17941	945	264	1209

सारणी--3

प्राथमिक स्तर पर अध्यापकों की संख्या

क्रम० सं०	जिले का नाम	कुल अध्यापक			केवल अनुसूचित जाति के अध्यापकों की संख्या		
		पुरुष	महिला	जोड़	पुरुष	महिला	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अम्बाला	644	1322	1966	45	83	128
2.	भिवानी	1244	1266	2510	124	40	164
3.	फरीदाबाद	1861	1458	3319	143	22	165
4.	गुड़गांव	1495	1592	3087	108	13	121
5.	हिसार	1874	2337	4211	304	84	388
6.	जीन्द	1862	1078	2940	153	17	167
7.	कैथल	1164	810	1974	54	13	67
8.	करनाल	912	1117	2029	91	33	124
9.	कुरुक्षेत्र	572	728	1300	55	14	69
10.	महेन्द्रगढ़	1178	604	1782	110	18	128
11.	पंचकुला	152	532	689	18	11	29
12.	पानीपत	806	777	1583	44	8	52

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	रिवाड़ी	1034	583	1617	93	10	103
14.	रोहतक	2099	2075	4974	174	59	233
15.	सिरसा	738	994	1732	129	16	145
16.	सोनीपत	1440	1700	3140	106	63	169
17.	यमुनानगर	672	825	1497	65	13	78
	जोड़ :	19752	20598	40350	1816	514	2330

सारणी–4

वर्ष 1995-96 में जिलावार प्राथमिक स्तर की छात्र संख्या (कक्षा 1 से 5)

क्रम० सं०	जिले का नाम		कुल छात्र संख्या		केवल अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या		
	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अम्बाला	42087	40667	82754	15431	14307	29738
2.	भिवानी	82268	60596	142864	16448	16112	32560
3.	फरीदाबाद	81903	66055	147958	17492	16226	33718
4.	गुड़गांव	73193	53597	126790	13741	11989	25730
5.	हिसार	112041	89289	201330	33551	25745	59296
6.	जीन्द	67661	52987	120648	16052	11834	27886
7.	कैथल	66354	50474	116828	17991	12673	30664
8.	करनाल	57610	52237	109847	16718	14297	31015
9.	कुरुक्षेत्र	35934	32571	68505	10348	9105	19453
10.	महेन्द्रगढ़	49296	45351	94647	9798	9592	19390
11.	पंचकुला	17297	15670	32967	4701	4214	8915
12.	पानीपत	44327	38439	82766	10475	8955	19430
13.	रिवाड़ी	34957	36755	71712	9017	9032	18049

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	रोहतक	97129	91505	188634	22762	21133	43875
15.	सिरसा	51473	44052	95525	15873	13470	29343
16.	सोनीपत	69432	61068	130500	15318	13500	28818
17.	यमुनानगर	42458	39164	81622	17269	1643	33712
जोड़		1025420	870477	1895897	262985	228607	491592

28882—D.P.I. (P)—H.G.P., Chd.

NIEPA DC
D09819

UMENT
Institute of
and Adm
Aurobind
Delhi-110016
DC, No.........
D-9819
03/3/98